रोहित त्रिपाठी
लोक-नीति विश्लेषक

मुफ्त बिजली योजना

राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका

बिहार सरकार प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना शुरू करने जा रही है। इस संबंध में विचारणीय है कि मुफ्त बिजली की यह राजनीति अब केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रही। दिल्ली, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में यह रुझान आम हो ताजा जा रहा है। सवाल यह है कि देश में मुफ्त योजनाओं, खासकर बिजली जैसी आधारभूत सेवाएं, सामाजिक न्याय की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है या फिर केवल सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी? दीर्घकाल में होने वाले इसके नुकसान को भी देखना-समझना होगा

लोकतुलाकार राजनीति की ही नतीजा है कि समय राज्य मुफ्त बिजली योजना को अपनाते जा रहे हैं। पाउल

बिहार में विधानसभा चुनाव में अब महज तीन माह का समय शेष है। हर माह 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की सरकार की घोषणा के साथ ही एक बार फिर मुफ्त बिजली का गूंज उठा है। सियासी गलियारों में तेज हो गई है। जो बयानबाजी में मुफ्त बिजली बोई गई बात नहीं है। पंजाब, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने समय-समय पर इस रणनीति को अपनाया है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इसी माडल को आधार बनाकर चुनावों में बढ़त पाई। अब सवाल यह है कि क्या बिजली मुफ्त देने से राज्यों की माली हालत पर असर पड़ेगा? क्या इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में बोझ नहीं बढ़ेगा? इस मुफ्त बिजली की कीमत कौन चुका रहा है? सरकार? जनता? आखिरकार यह बोझ हो तो करदाताओं के कंधों पर ही पड़ता है यहां वे लाभ लें या न लें।

यह समझना जरूरी है कि मुफ्त बिजली का अर्थ केवल फ्री यूनिट देना नहीं है, बल्कि यह नियंत्रित वित्तीय अनुशासन, बौद्धिक संसाधन और सामाजिक न्याय तीनों से जुड़ा है। यदि यह योजना लक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से लागू की जाती है, तो यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक सकारात्मक पहल हो सकती है। लेकिन यदि यह सभी वर्गों को मुफ्त बिजली आधिक आधार के समान रूप से दे दी जाती है, तो यह केवल बोझ बढ़ाने का काम करेगा और इसे वापस लौटाना कठिन हो जाएगा। यह सही है कि समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना सरकार का नैतिक दायित्व है। कल्याणकारी राज्य प्रदान करना इस कर्तव्य को पूरा करने के रूप में देखा जा सकता है, विशेषकर गरीबी और असमानता को दूर करने में। हालांकि, वास्तविक कल्याण और लोक हित सरकार के उद्देश्य से भी जाने वाले लोक-लुभावनीकरण के बीच एक महीन रेखा है। बिहार पहले से ही राजस्व घाटे से जूझ रहा है। ऐसे में यदि सरकार हर महीने करोड़ों यूनिट बिजली मुफ्त देती है, तो इसका सीधा असर शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और अन्य जरूरी सेवाओं के बजट पर पड़ेगा।

यह सोचा जाना चाहिए कि क्या बिजली उपभोग की आदतों को भी उलटा सकेगा। जब किसी संसाधन को कोई कीमत नहीं होती, तो उसका दुरुपयोग स्वाभाविक है। इसलिए न केवल बिजली की खपत अनावश्यक रूप से बढ़ती है, बल्कि वितरण तंत्र पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कई मामलों में देखा गया है कि मुफ्त बिजली का लाभ मध्यम और उच्च आयवर्ग के लोग भी उठा लेते हैं, जिससे असली जरूरतमंद वंचित रह जाते हैं।

यह सही है कि प्रत्येक लाभ लेने वालों से मांग को बढ़ाया मिलता है तथा क्रय शक्ति में वृद्धि होती है और व्यय में वृद्धि के कारण से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा सर्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और मध्यह्न भोजन जैसी खाद्य सुरक्षा योजनाएं बुनियादी जीविका सुनिश्चित करने के साथ गरीबों को कम करने में भूमिका निभाती हैं। सब्सिडियां और लीकेज जैसी चुनौतियां बनी रहती हैं। ऐसे में यदि राज्य सरकार इस तरह की योजनाओं का पूरा बोझ उठाएगी, तो वह अपने अन्य प्राथमिकताओं से समझौता करने के लिए विवश होगी। इस संदर्भ में नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के विशेषज्ञ कई ऐसे ढांचे की परिकल्पना करनी चाहिए जो मुफ्त योजनाओं की सीमा और वित्तीय सीमा स्पष्ट रूप से तय करे। सीएसआर, कार्बन टैक्स या ऊर्जा क्षतिपूर्ति फंड आदि की भी भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए।

यह सच है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को जनहित की योजनाएं बनाने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार जवाबदेही के साथ आता है। अल्पकालिक चुनावी लाभ को ध्यान में रखकर दी जाने वाली मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं भले ही तुरंत राहत दें, लेकिन दीर्घकालिक विकास पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं। बिहार सरकार को घोषणा निष्पक्ष रूप से बड़ी संख्या में लोगों को राहत पहुंचाएगी। लेकिन यह भी उठना ही जरूरी है कि योजना की आर्थिक लागत कैसे निकाली जाएगी और सुनियोजित बनाया जाए। मुफ्त योजनाएं तब तक ही लोकल्याणकारी हैं, जब तक वे जरूरतमंदों को राहत देती हैं और राजकोष पर अस्वाभाविक बोझ नहीं डालतीं। यदि यह केवल चुनावी 'ट्रांजेक्ट' का हिस्सा बनकर रह जाएं, तो वे संसाधनों का दुरुपयोग, आर्थिक असंतुलन और नीति विकृतियों को मिसाल बन सकती हैं। कुल मिलाकर प्रश्नोत्तर यह आर्थिक निर्भरता के अवसर, सरकार से सामाजिक सुरक्षा तंत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना उचित्त होगा। यदि, मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं लागू करनी ही हैं, तो इसे एक सशर्त योजना के रूप में लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए उपभोक्ता की आय, घरेलू आवश्यकता, ऊर्जा दक्षता और पारदर्शिता को आधार बनाया जाना चाहिए। साथ ही, इसके प्रभाव का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, राज्य सरकारों को अपने बजट में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान करने चाहिए। यह योजना राज्य के वित्तीय संसाधनों को प्रभावित न करे, इसके लिए वैकल्पिक स्रोतों की पहचान की जानी चाहिए। इसके अलावा, सरकार को अपने बजट में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान करने चाहिए। यह योजना राज्य के वित्तीय संसाधनों को प्रभावित न करे, इसके लिए वैकल्पिक स्रोतों की पहचान की जानी चाहिए। इसके अलावा, सरकार को अपने बजट में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान करने चाहिए। यह योजना राज्य के वित्तीय संसाधनों को प्रभावित न करे, इसके लिए वैकल्पिक स्रोतों की पहचान की जानी चाहिए।

फिर से

कहां गई गौरैया...

'अब हमें गौरैया कहीं नहीं दिखती?' मन को छूता हुआ यह सवाल, लेकिन अब तो अरुढ़ के दिनों में पुर्वजों की खिलाने के लिए बचैये, जो कच्चे रोशनमें की दिलेरी हुआ करते थे, आस-पास से गायब हो गए हैं। प्रदूषण से गायब हुए। पेसा बोलना बहुत आसान लगता है, लेकिन संभवतः यही कड़वा सच भी है। परंतु क्या पुरा सच है?

हर साल पुक्षी दिवस या पर्यावरण दिवस एक औपचारिक समारोह के रूप में जीव-जाख ही मान रहे हैं- पौधा लगाकर, ईंटरनेट मीडिया पर पोस्ट शेयर करके जागरूक कर के, सेमिनार कर कर, खाड़ी की महरी साहित्य, कुछ आदि पढ़कर कर, निबंध ज्ञान होने की प्यासकता देखिए, पुछ लीजिए स्वयं से कभी जैसे हर बार अपने बच्चों से चक्कनी का हिसाब पूछते हैं। हम क्या लगा रहे हैं? हम इसे क्या कर रहे हैं? हम इसे क्या लगा रहे हैं? और क्या हम इसे सही तरीके से कर रहे हैं?

असली नुकसान तो कहीं और हो कर रहे हैं। ज्ञान के अभाव में प्रकृति के विकास से रुकेंगे को कहाने कर हैं- बिना इसका अहसास किए। अपने बगीचों, बालकनियों, पार्कों और परिसरों को ऐसे सजावटी पौधों से भर रहे हैं जो देखने में भले ही अच्छे लगें, लेकिन हमारी धरती के अनेक गौरैं में बैर जाकर हैं। उन परिस्थितिक तंत्रों को तहस-नहस कर रहे हैं जो कभी पक्षियों, कीड़ों और यहां तक कि हमारे घरेलू मौसमों की प्रकृतिक लय को बनाए रखते थे। चेड़ी की चिड़ियां, तोते, कौवे और उनके जीवनचक्र के बारे में न जानकर एक सपाट के ज्ञान को खो रहे हैं। ऐसे पेड़ उगाने का महत्व जो हमारी मिट्टी, हमारे पक्षियों, हमारी जलवायु के लिए हैं- अब केवल गीतों तक सीमित हो गए हैं, और वहां भी, यह सवाल के साथ शहरों की पत्रकारीय के बारे में कौवे क्या हो गए?

कैसे हो सोचें कि क्या हमारी स्थानीय नर्सरियां और बागानी हमें मार्गदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित हैं? क्या उन्हें पता है कि क्या सुझाव देना है- और उसमें भी महत्वपूर्ण बात, कर्वों? आर्टिफिशियल हिमाचल के गुण गाया- चिड़ियों के लिए बालकनी तो सैटेयीयो आयात करती ही रहेंगे। इस सच चोजों के बारे में क्या हमें फिर से विचार नहीं करना चाहिए?

(डा. गुंजन राजपूत की फेसबुक वाल से संपादित अंश, साभार)

पोस्ट

अरुण आर्य
राण पुरो झुग, बिहार

बिहारसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार का यह मैसर्स आप्रवर्तनक लग सकता है। दो बड़े गठबंधन-एनडीए और महागठबंधन के बीच में 'पर्चा' होती है कि इनमें से किसको सरकार बनेगी। इन दोनों के बीचोंबीच एक पर्चा चलती है कि प्रवर्ति किशोर किस गठबंधन का बन्ड बनाएंगे, क्या बिगड़ेंगे। यह बिल्कुल वो तीसरी घर है, जिस पर सबसे अधिक समय बरबाद किया जाता है। दो बड़े गठबंधनों को एक प्रवर्ति किशोर को पर्चा लगाने के चक्कर में यह नहीं कहा जा रहा है कि इन नई पार्टी को भी सरकार बन सकती है। अपनी पार्टी की अच्छी पुनर्वी संघनाओं को चार में पोंके राज्य का प्रमाण कर रहे हैं। उनको पार्टी की संघनाएं बड़ी है। भाए उत्कर्ष टॉर्च बनाकर के जोतों को भी परेशानी हो रही है। टोंगे गठबंधन यह सोचकर बाहरी रूप में निश्चित नजर आ रहे हैं कि राज्यों को ऐसी में नाराज हो जाएं। क्या पुरा बिहार और पोंके के बीच कुछ पता है? इस प्रश्न को पिथुरा और पोंके के बीच कुछ पता हो? इस प्रश्न को पिथुरा और पोंके के बक्तपत्रों में मजबूती मिलती है, जिसमें एक दूसरे पर प्रहार का कोई अंश उपलब्ध नहीं होता है। दूसरी तरफ एनडीए के बोर-गोर नेता इन आरोपों को इन टिप्पणियों में रद कर देते हैं- यह सब बिहारसभा में अपने दल के लिए अधिक सीट लेने के लिए है। मोलतोल के बाद मन्त्रमाडिक सीटें मिल जाएंगी तो पिथुरा कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि निश्चित तो तीहु अनिश्चित्त को और जाने का खतरा घात कोन समझदार उठाता है। निश्चित यह कि कांचन सामेकना में बैठाने कैंडिट्स में पिथुरा का पद सुरक्षित है। राज्य में अगली सरकार एनडीए की बनाते है तो पिथुरा की पार्टी के विधायकों को भी उसमें जगह मिल सकती है। पिथुरा के साथ के पोंके लोग, जिन्हें टिकट मिलने की गारंटी है, एनडीए से अलगाव नहीं चाह रहे हैं। बनाने वाले नहीं, जिताड़ने वाले एक हथियार पोंके के रूप में जा सकता है। लेकिन, यह भी देखो गठबंधनों की बात से उम्मीदवारों के चयन में शेनेवाली चूक पर निर्भर है। महागठबंधन के दोनों के बीच जिस तरह से सीटों को लेकर ध्यानान है, यह जाने वाला तय है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जैसे जिस तरह से सीटों को लेकर ध्यानान है, यह जाने वाला सक्षम उम्मीदवार इस बार टिकट से वंचित रह जाएंगे। इसके अलावा, दोनों को अंदरूनी कलह का खतरा भी इस योग उम्मीदवार बेटिकट हो सकते हैं। लगभग वही स्थिति एनडीए के घटक दलों के बीच भी है। एनडीए में किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, यह प्रश्न अनुत्तरित है। अधिक उम्र के कारण भी कुछ विधायक रुकावट जा सकते हैं। वहीं, एनडीए के कुछ नेताओं पर टिकट के लिए अपनी सीटों को धोबरस्त दबाव है। टिकट की आस में ऐसे क्षेत्र में दंड गए हैं। दोनों गठबंधनों के पेशे ही बेटिकट उम्मीदवारों के दम पर पोंके कुछ कर सकते हैं। कोई गठबंधन इस गुमान में रहे कि बेटिकट होने पर प्रतिष्ठ नेतृत्व के दम पर ही पिथुरा है, वह अंतत: धम्म ही प्रमाणित होता है। पिथुरा पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में इसे प्रमाणित कर दिखा दिया है। उस समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोंड़ी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाम मात्र चुनाव प्रचार कर रहे थे। परिणाम आया तो एनडीए की सरकार मुश्किल से बन पाई। यह ठीक है कि पिथुरा की पार्टी कुछ हार का शिकार हुई।

इस समय पुरानी दोनों गठबंधनों के उम्मीदवार के नाम तय होने में बहुत देर है, पोंके की 2020 जैसी पिथुरा की भूमिका की कल्पना तो की ही जा सकती है। हां, इस चेतनवने के साथ कि पोंके किसी भी गठबंधन के लिए पिथुरा पासवान प्रमाणित हो सकते हैं। दोनों घर में गठबंधनों की तरफ से उम्मीदवारों के चयन में असंतुष्टों बड़ती जाए। असंतोष बढ़ाने वाली गतिविधि की जाए।

सहकारिता नीति

नए भारत के निर्माण में योगदान

डॉ. कन्नैया त्रिपाठी
वरिष्ठ प्रोफेसर, केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब एवं राष्ट्रपति के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी

गुरुवार को राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 राष्ट्र को समर्पित की गई है। देश के समग्र विकास की दिशा में यह एक प्रभावी कदम है। इससे देश के विकास की गतिविधि तीव्र हो जाएगी

लगभग 23 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिर देश को नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति मिल गई है। इसका उद्देश्य सहकारिता के सशक्त प्रभाव अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है साथ में स्थापित करके भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस नीति का मसौदा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से विमर्श के बाद तैयार किया गया है। वहीं गुजरात के आणंद में हाल ही में त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय का भूमि-पूजन हो चुका है।

संसुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसको थीम है- सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय जैसी संस्थान इस पूरी योजना को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हुए जन-केंद्रित और आत्मनिर्भर सहकारी उद्यमों का समर्थन है एवं एक ऐसे पोढ़ी का निर्माण करने की कोशिश है जिससे भारत के सभी हितधारक सहकारिता के माध्यम से आगे चलो पोढ़ियों के जीवन को समृद्ध कर सकें। सहकारिता वर्ष को थीम जब ही गई थी तो यह सैद्ध गया था कि एक ऐसी रानीति बने जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा देकर सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करने और सहकारी समितियों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाया जा सके।

अमेय सिद्धि : देखा जाए तो क्रम का अपना मूल्य होता है। श्रम किसी से संबंधित है। इसमें सम्मान रहता है- अमेय सिद्धि। इसमें देश में सहकारिता एक बेहतर विकल्प बन कर उभर कर आयोगित है। ऐसे में एक पूर्ण सहकारिता श्री अमित शाह 'श्रम से सिद्धि' के साथ 'सहकार से सिद्धि' का अभिनव तोहफ़ा भारत को उपहार कर रहे हैं। आने वाला समय सहकारिता का समय है। सहकारिता के पैरोकारों की इसलिए अपने समर्पित मन से इस दिशा में सौपने की आवश्यकता होगी। किसी भी राष्ट्र का निर्माण उस भूमि पर रहने वाले जीवंत लोगों से सुनिश्चित होता है। हमारे सहकार से समृद्धि का स्वप्न तभी पूरा हो सकेगा, जब हम सहकारिता के पैरोकारों की संख्या में वृद्धि करें। वह पहल करें, नए आयामों पर विचार करें।

सहकार विजय का त्रिभुवन : आज पूरी दुनिया यह जान चुकी है कि सहकारी उद्यम लोगों को सशक्त बनाते हैं, समुदायों को मजबूत करते हैं। लोकतंत्र, मानव गरिमा, एकजुटता और विकास के मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। साथ विरासत चलाने की खुली और सहकारिता से जीवन को सेवकरने की कोशिश वर्ष 1923 से शुरू है। अब तो दुनिया में बहुत बदलाव हुआ है। नए तकनीकी विकास व एकजुट संघर्ष ने सभी को एकीकृत किया है। अब सहकारिता को आसमने से मजबूत किया जा सकता है। एकीकृत होकर नई उपलब्धियों हेतु पेंटा-भेकर की धुधियां में अपनी युवा पीढ़ी को सम्मिलित करने की बारी है। भारत अपने युवा जनसंख्या को यदि सहकारिता से जोड़ लेते तो दुनिया में भारत युक्त सहकारिता अंदोलन के जरिए हो बहुत कुछ शिखरत करने की स्थिति में आ जाएगा।

इसी साल संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यह विमर्श हुआ कि कैसे सहकारी समितियां 2030 एजेंडा और आगामी विश्व सहकारिक शिखर सम्मेलन के अनुरूप समावेशी, सतत विकास को आगे बढ़ा सकती हैं। इस समय दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें जलवायु परिवर्तन, जलवायु आपातकाल, आर्थिक झटके, संघर्ष और विस्थापन के कारण, सरकार को सहकारिक सुरक्षा तंत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना उचित्त होगा। यदि, मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं लागू करनी ही हैं, तो इसे एक सशर्त योजना के रूप में लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए उपभोक्ता की आय, घरेलू आवश्यकता, ऊर्जा दक्षता और पारदर्शिता को आधार बनाया जाना चाहिए। साथ ही, इसके प्रभाव का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, राज्य सरकारों को अपने बजट में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान करने चाहिए। यह योजना राज्य के वित्तीय संसाधनों को प्रभावित न करे, इसके लिए वैकल्पिक स्रोतों की पहचान की जानी चाहिए। इसके अलावा, सरकार को अपने बजट में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान करने चाहिए। यह योजना राज्य के वित्तीय संसाधनों को प्रभावित न करे, इसके लिए वैकल्पिक स्रोतों की पहचान की जानी चाहिए।

सौर ऊर्जा : एक टिकाऊ समाधान की तलाश

ऊर्जा क्षेत्र में आयातियों और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है देशभर में पूर्वी की छतों पर सोलर पैनल लगाकर न केवल हमें बिजली उपलब्ध कराना, बल्कि घर परिवार की ऊर्जा उत्पादक बनाना। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के अंतर्गत 30 गीगावाट सौर क्षमता विकसित की जाए, जिससे अगले 25 वर्षों में लगभग एक हजार अरब यूनिट बिजली का उत्पादन संभव होगा। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ऊर्जा क्षेत्र के साथ ही यह आमदनी का साधन भी बन सकती है।

सरकार के अनुसार, एक औसत तीन किलोवाट का रूफटाप सोलर सिस्टम हर महीने करीब तीन सौ यूनिट बिजली पैदा कर सकता है, जो अधिकांश घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। इससे बिजली बिल में भारी कटौती होगी। यदि यह केवल चुनावी 'ट्रांजेक्ट' का विराटरा कंपनियों (डिस्कॉम) को बेचकर परिवार अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। यह पहल मध्यमवर्गीय और किसानवीय परिवारों के सीधा आर्थिक लाभ दे सकती है, जिससे उनकी बिजली उपभोग की लागत में काफी कमी आ सकती है। यानी ओरतरीयोग जलवायु प्रतिबद्धताओं की दिशा में भी ठोस तौर से आगे बढ़ रहा है।

वैसे कुछ चुनौतियां इसे पूर्ण सफलता तक पहुंचाने के रोक सकती हैं। यदि राज्यों में मुफ्त बिजली दे जा रही है, जिससे लोग निजी सौर प्रणाली लगाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जब उन्हें बिना कोई निवेश किए मुफ्त बिजली मिल रही हो, तो वे ऐसा होने स्वाभाविक है। यदि सही ढंग से लागू किया जाए, तो यह योजना भारत के ऊर्जा परिदृश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है और हर घर को ऊर्जा-आत्मनिर्भर बना सकती है। **(रोहित त्रिपाठी)**

वैसे ये सौर ऊर्जा संयंत्रों की रखरखाव, सर्विसिंग और सामाजिक भूमिकाएं भी बेहतर कुशलता से निपटाते हुए सौर ऊर्जा को मजबूती करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे गुरुकलाएं स्वास्थ्य देखभाल, सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली, रोजगार सृजन और व्यापक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ताकि सामाजिक-आर्थिक असमानता में बड़े कारणों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके।

विमर्श 9

पोस्ट

किसका क्या बनाएंगे- बिगाड़ेंगे प्रशांत किशोर

मुजफ्फरपुर में एक जनसभा के दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रशांत किशोर। पाउल

इसी क्रम में यह प्रश्न भी पूछा गया जाता है- क्या जिनपुर और पोंके के बीच कुछ पता हो? इस प्रश्न को पिथुरा और पोंके के बक्तपत्रों में मजबूती मिलती है, जिसमें एक दूसरे पर प्रहार का कोई अंश उपलब्ध नहीं होता है। दूसरी तरफ एनडीए के बोर-गोर नेता इन आरोपों को इन टिप्पणियों में रद कर देते हैं- यह सब बिहारसभा में अपने दल के लिए अधिक सीट लेने के लिए है। मोलतोल के बाद मन्त्रमाडिक सीटें मिल जाएंगी तो पिथुरा कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि निश्चित तो तीहु अनिश्चित्त को और जाने का खतरा घात कोन समझदार उठाता है। निश्चित यह कि कांचन सामेकना में बैठाने कैंडिट्स में पिथुरा का पद सुरक्षित है। राज्य में अगली सरकार एनडीए की बनाते है तो पिथुरा की पार्टी के विधायकों को भी उसमें जगह मिल सकती है। पिथुरा के साथ के पोंके लोग, जिन्हें टिकट मिलने की गारंटी है, एनडीए से अलगाव नहीं चाह रहे हैं।

बनाने वाले नहीं, जिताड़ने वाले एक हथियार पोंके के रूप में जा सकता है। लेकिन, यह भी देखो गठबंधनों की बात से उम्मीदवारों के चयन में शेनेवाली चूक पर निर्भर है। महागठबंधन के दोनों के बीच जिस तरह से सीटों को लेकर ध्यानान है, यह जाने वाला तय है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जैसे जिस तरह से सीटों को लेकर ध्यानान है, यह जाने वाला सक्षम उम्मीदवार इस बार टिकट से वंचित रह जाएंगे। इसके अलावा, दोनों को अंदरूनी कलह का खतरा भी इस योग उम्मीदवार बेटिकट हो सकते हैं। लगभग वही स्थिति एनडीए के घटक दलों के बीच भी है। एनडीए में किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, यह प्रश्न अनुत्तरित है। अधिक उम्र के कारण भी कुछ विधायक रुकावट जा सकते हैं। वहीं, एनडीए के कुछ नेताओं पर टिकट के लिए अपनी सीटों को धोबरस्त दबाव है। टिकट की आस में ऐसे क्षेत्र में दंड गए हैं। दोनों गठबंधनों के पेशे ही बेटिकट उम्मीदवारों के दम पर पोंके कुछ कर सकते हैं। कोई गठबंधन इस गुमान में रहे कि बेटिकट होने पर प्रतिष्ठ नेतृत्व के दम पर ही पिथुरा है, वह अंतत: धम्म ही प्रमाणित होता है। पिथुरा पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में इसे प्रमाणित कर दिखा दिया है। उस समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोंड़ी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाम मात्र चुनाव प्रचार कर रहे थे। परिणाम आया तो एनडीए की सरकार मुश्किल से बन पाई। यह ठीक है कि पिथुरा की पार्टी कुछ हार का शिकार हुई।

इस समय पुरानी दोनों गठबंधनों के उम्मीदवार के नाम तय होने में बहुत देर है, पोंके की 2020 जैसी पिथुरा की भूमिका की कल्पना तो की ही जा सकती है। हां, इस चेतनवने के साथ कि पोंके किसी भी गठबंधन के लिए पिथुरा पासवान प्रमाणित हो सकते हैं। दोनों घर में गठबंधनों की तरफ से उम्मीदवारों के चयन में असंतुष्टों बड़ती जाए। असंतोष बढ़ाने वाली गतिविधि की जाए।

प्रशांत किशोर जुड़वाह : राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जो सहकार से समृद्धि की कहानी रच रही है, इसके एक और पहलू पर भी विचार होना चाहिए खेती को बढ़ावा देने से इंसान और पशुओं की सेहत अच्छी रहती की अपहुर्ष कोशिश की जा रही है। इससे पानी का बचाव करते हुए अनाज के उत्पादन में वृद्धि होगी। भारतीय सहकारिता में इस प्रकार केवल मजूरा की चिंता नहीं है, अपितु सबसे भाओ में प्रकृति, धरती और जीव व जीवन की पुनर्बहाली करने की पेशा है। संपूर्णता में देखें तो सहकारिता का सहकार या यह प्रयास भरत में समाविशता को आगे बढ़ाने जा रहा है, जिससे देश के विकास की गतिविशता भी कई गुना बढ़ जाएगी।

****